HRCI AN USIUS The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224]

No. 224]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 29, 1999/बैशाख 9, 1921 NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 29, 1999/VAISAKHA 9, 1921

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1999

का.आ. 290(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार यह निर्धारित करने के लिए क्या आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और नेशनल लिब्रेशन फ्रंट आफ इंडिया को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, एतदृद्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री बिजेन्द्र जैन की अध्यक्षता में एक ''विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण'' का गठन करती है।

> [फा. सं. 9/26/98-एन. ई.-1] जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 1999

S. O. 290(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes "The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Shri Justice Vijender Jain, Judge of the Delhi High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the All Tripura Tiger Force and National Liberation Front of Tripura, as unlawful associations.

[File No. 9/26/98-N.E.I]

G. K. PILLAI, Jt. Secy.